राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

चीन पर अंकुश के लिए एशिया में तैनात होंगी अमेरिकी मिसाइलें : एस्पर

>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 55

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 4 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

मुफलिसी की दीवार तोड़ बनाया समृद्धि का रास्ता

हरदोई : उत्तर प्रदेश में हरदोई के एक गांव के भूमिहीन और कम जोत वाले परिवार की महिलाओं ने मुफलिसी की दीवारों को तोड़कर समृद्धि का रास्ता बना डाला।

आज ये महिलाएं ट्रैक्टर-ट्रॉली, रोटावेटर कल्टीवेटर, हैरो, स्प्रेयर, थ्रेशर, पंपसेट आदि की मालकिन हैं। (पेज-13)

रविवार विशेष

अब हवा की नमी से भी पैदा हो सकेगा पानी

अल्मोड़ा : राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन की परियोजना के तहत आइआइटी मंडी के वैज्ञानिकों ने हवा से पानी तैयार करने की तकनीक विकसित की है।

इससे आठ से दस घंटों में करीब छह लीटर पानी एकत्र किया जा सकेगा। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विचारधारा के बल पर यहां तक पहुंची है भाजपा : मोदी

नई दिल्ली : भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि पार्टी किसी परिवार के बल पर नहीं, बल्कि विचारधारा के बल पर इस मुकाम तक पहुंची है। सांसदों को कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बदौलत ही वे यहां तक पहुंच पाए हैं। अभ्यास वर्ग में मोदी, पार्टी अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

अगस्त में चौतरफा अच्छी बारिश के आसार

नई दिल्ली : मानसून पूरे देश पर छा गया है, लेकिन कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। हालांकि देश का कुछ हिस्सा अभी भी सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है, जिससे कुछ चिंताएं बढ़ी हैं। बारिश में कमी के चलते खरीफ सीजन की फसलों की बोआई प्रभावित हुई है। इससे खेती की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले पीछे चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अगस्त माह में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

अर्थव्यवस्था में मंदी के खिलाफ हथियार बनेगा सस्ता कर्ज

नई दिल्ली : दुनियाभर के देश सुस्ती से लड़ने के लिए सस्ते कर्ज का हथियार आजमाते हैं। भारत भी इस हथियार को आजमाने में ज्यादा चुस्ती दिखाने जा रहा है। अगले हफ्ते सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण की बैंक प्रमुखों के साथ होने वाली बैठक और उसके बाद बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक में ब्याज दर को घटाना एक अहम मुद्दा रहेगा। उम्मीद है कि सरकार इसके जरिये राहत देने की कोशिश करेगी।

कैरिबियाई चुनौती

टी-20 सीरीज

वेस्टइंडीज vs भारत

रात 8:00 बजे से

स्थान : लॉडरहिल, अमेरिका

प्रसारण : सोनी नेटवर्क

पूरे देश में एनआरसी की तैयारी, डाटाबेस के लिए हर बाशिंदे की होगी पहचान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को देशभर में लागू करने से पहले उसका आधार तैयार करने के लिए सितंबर, 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का फैसला किया है। भारत के प्रत्येक निवासी को एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस कवायद का मकसद देश में रहने वाले हर सामान्य निवासी की पहचान का व्यापक डाटाबेस तैयार करना है। इस डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ-साथ बायोमीट्रिक जानकारियां भी होंगी।

एक अधिकारी ने बताया कि एनपीआर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होगी। एक बार जब एनपीआर तैयार होकर प्रकाशित हो जाएगा तो संभावना है कि यह असम एनआरसी के देशव्यापी संस्करण 'नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजंस' (एनआरआइसी) को तैयार करने का आधार बनेगा।

ये होंगे एनपीआर में शामिल : एनपीआर के लिए एक सामान्य निवासी उसे माना जाएगा जो उस स्थानीय इलाके में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो अथवा जो उस इलाके में छह महीने या इससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता हो।

घर-घर जाकर जुटाई जाएंगी जानकारियां : महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, 'नागरिकता (नागरिकों के पंजीयन एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी) नियमावली, 2003 के नियम तीन के उपनियम चार के तहत केंद्र सरकार ने जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अपडेट करने का फैसला किया है।' साथ ही इसमें कहा गया है कि असम को छोड़कर देशभर में घर-घर जाकर गणना करने और सभी लोगों की जानकारियां एकत्र करने के लिए फील्ड वर्क एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। एनपीआर को स्थानीय (ग्राम/कस्बा), अनुमंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।

- सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करेगी सरकार
- प्रत्येक निवासी के लिए पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य
- डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारियां भी होंगी

एक अप्रैल, 2020 से शुरू होगा काम। फाइल

अभिभाषण में राष्ट्रपति ने किया था एलान : नई लोकसभा (17वीं) के गठन के बाद 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं का उल्लेख किए जाने के करीब महीनेभर बाद यह कदम उठाया गया है। कोविंद ने कहा था, 'मेरी सरकार ने घुसपैठ प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर एनआरसी की प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है।'

असम में प्रक्रिया जारी इसलिए शामिल नहीं : असम को इसमें शामिल नहीं किए जाने की वजह यह है कि वहां एनआरसी की प्रक्रिया पहले से चल रही है। मालूम हो कि असम में पिछले साल 30 जुलाई को जब एनआरसी का मसौदा प्रकाशित किया गया था तब 40.7 लाख लोगों को इससे बाहर किए जाने पर काफी विवाद हो गया था। इसके बाद इस सूची की पुष्टि करने की प्रक्रिया चल रही है।

तलाशे जा रहे 35ए में बदलाव के विकल्प

चर्चाओं के बीच ▶ अनुच्छेद 370 को भी समाप्त किए बिना हो सकता है अहम संशोधन

सोच यह कि निजी निवेश आकर्षित कर विकास की गति तेज करना होगा संभव

नीलू रंजन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ अमरनाथ यात्रियों, पर्यटकों और बाहर के छात्रों को घाटी से निकालने की कोशिशों के बीच कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। इनमें अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने से लेकर राज्य को तीन भागों में विभाजित करने तक की बातें की जा रही हैं। कश्मीर मामलों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मानें तो सरकार अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के बजाय उनमें जरूरी संशोधनों के साथ भी आगे बढ़ सकती है। इससे जहां कश्मीर के भीतर इन अनुच्छेदों को हटाने को लेकर हो रहे विरोध के स्वर कमजोर होंगे, वहीं इनके कारण विभिन्न वर्गों के साथ हो रहे पक्षपात को समाप्त करने और निजी निवेश को आकर्षित कर विकास की गति को तेज करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ महीनों के भाषणों को ध्यान से देखने की सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने 370 और 35ए की आलोचना सिर्फ इस आधार पर की है कि इसके कारण पिछले 70 साल में कश्मीर का विकास नहीं हो सका। पिछले हफ्ते अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने बताया था कि किस तरह कश्मीर की आम जनता विकास और अमन चाहती है। उन्होंने कहा था, 'जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, वे कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते।'

कश्मीर पर नीति निर्धारण से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए राजनीतिक मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह निरस्त किए बिना भी जरूरी लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 निजी निवेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यदि इसमें संशोधन कर निवेश की इच्छुक कंपनियों और व्यक्तियों को लंबी लीज पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया जाए तो राह आसान हो जाएगी। इसी तरह, 35ए में संशोधनों के साथ राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता से रोकने जैसे प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अनुच्छेद 370 और 35ए को पूरी तरह निरस्त करने के बजाय इसमें संशोधनों के साथ आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। अनुच्छेद 370 के लिए सरकार को संवैधानिक संशोधन का रास्ता चुनना होगा। जबकि 35ए में संशोधन के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी। यहां सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सरकार 35ए में संशोधनों के साथ आगे बढ़ सकती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट को इन संशोधनों की जानकारी दे सकती है। 35ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन अनुच्छेदों को हटाने का विरोध करने वाले कश्मीरी नेता भी अब इनमें संशोधनों की बात करने लगे हैं। उन्होंने पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साक्षात्कार हवाला दिया। इसमें फारूक साफ-साफ 35ए में संशोधन की जरूरत स्वीकार रहे हैं। उनकी शर्त सिर्फ इतनी है कि यह संशोधन जम्मू-कश्मीर विधानसभा से कराया जाए और उसके लिए पहले विधानसभा चुनाव हों।

जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ अफवाहों के बीच अमरनाथ यात्री, पर्यटक और बाहरी छात्र घाटी छोड़ने लगे हैं। शनिवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बसों से वापस लौटने लगे। एएनआइ

50 हजार पर्यटक, श्रद्धालु और कामगारों को घाटी से बाहर भेजा गया पेज>>4

कश्मीर में एलओसी पर बैट का बड़ा हमला नाकाम, सात ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बैट (बॉर्डर एक्शन टीम) दस्ते ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के केरन (कुपवाड़ा) सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक भारतीय सैन्य चौकी पर हमले का प्रयास किया, जिसे सेना ने नाकाम बना दिया। बताया जा रहा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में बैट के पांच से सात सदस्य मारे गए हैं। पिछले दस दिनों में इस क्षेत्र में बैट दस्ते का यह दूसरा हमला नाकाम किया गया है।

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, केरन सेक्टर में केल कुल्लियां इलाके से पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते ने भारत की एक अग्रिम निगरानी चौकी पर बड़ा हमला करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की। भारत की निगरानी चौकी में तैनात सतर्क जवानों ने बैट दस्ते को देख लिया। जैसे ही बैट दस्ता एलओसी से आगे पहुंचा, जवानों ने उसे ललकारते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाकर भागते हुए बैट दस्ते के सदस्यों को एलओसी के पास गिरते देखा गया है। सूत्रों ने बताया कि बैट दस्ते में करीब सात सदस्य शामिल थे। शायद ही कोई सदस्य जिंदा बचा हो। दो शव एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की सीधी फायरिंग रेंज में पड़े हैं और चार से पांच शव पाकिस्तानी इलाके में ही हैं। उन्होंने बताया कि एलओसी पर पड़े दोनों शवों को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। उधर, पाकिस्तानी सेना ने शनिवार देर शाम पुंछ के मेंढर व बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। शाम करीब सवा आठ बजे पाकिस्तानी सेना ने दोनों सेक्टरों में एकाएक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर मोर्टार दागना शुरू कर दिए। इससे सीमांत क्षेत्रों में दहशत फैल गई।

केरन सेक्टर में शनिवार को सेना ने पाकिस्तानी बैट के कई सदस्यों को ढेर कर दिया। नियंत्रण रेखा पर पड़े बैट सदस्यों के शव। एएनआइ

शोपियां और सोपोर में जैश के तीन आतंकी मार गिराए

श्रीनगर : आतंकवाद के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार से जारी मुठभेड़ में जिंदा बचे दूसरे आतंकी को मार गिराया तो सोपोर में जैश-ए-मुहम्मद के दो आतंकियों को ढेर कर दिया।

छत्तीसगढ़ में पांच महिलाओं समेत सात नक्सली मारे गए

राजनांदगांव, नईदुनिया

- मारे गए नक्सलियों पर था 32 लाख रुपये का इनाम, सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों के शव किए बरामद

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र की सीमा से सटी दो पहाड़ियों के बीच शनिवार को हुई मुठभेड़ में सात नक्सली मारे गए। इनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। इन नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने इस इलाके में सक्रिय दर्रेकसा एरिया कमेटी के शीर्ष लड़ाकों को खत्म कर देने का दावा किया है। मुठभेड़ में गातापार थाने में तैनात जवान आशाराम क्रती को भी गोली लगी है, जिन्हें डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया है। उन्हें रायपुर रेफर किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शेरपार और सीतागोटा पहाड़ियों पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर शुक्रवार को जिला पुलिस बल, डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त फोर्स को चार टीम में बांटकर रवाना किया गया।

निरीक्षक लक्ष्मण केंवट थाना प्रभारी गातापार के नेतृत्व में निकली चौथी टीम शनिवार सुबह आठ बजे जैसे ही सीतागोटा और शेरपार के बीच की पहाड़ियों पर पहुंची, घात लगाए नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब एक घंटे की फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। घटनास्थल की तलाशी लेने पर सात नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हुए हैं। आइजी हिमांशु गुप्ता ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को 50 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा कर बधाई दी है। मारे गए नक्सलियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं।

बड़ी वारदात को अंजाम देने की कर रहे थे तैयारी

28 जुलाई से नक्सलियों का शहीदी सप्ताह चल रहा है। इसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए करीब दस नक्सली घटनास्थल पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए टेंट लगाकर बैठक ले रहे थे। यह वही इलाका है, जिसे नक्सलियों ने ग्रीन कॉरिडोर बना रखा है। यहीं से गोंदिया, महाराष्ट्र, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में नक्सलियों की आवाजाही होती है।

आरोपित विधायक सेंगर और उसके भाई से घंटों पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उन्नाव (माखी) दुष्कर्म कांड की पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना के मामले की जांच सीबीआइ की टीम ने शनिवार को और तेज कर दी। जांच एजेंसी ने चार जिलों में दिनभर छानबीन की। सीतापुर जेल में बंद भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से टीम ने छह घंटे तक पूछताछ की। सीबीआइ के कई सवालों पर सेंगर चुप्पी साधे रहे। लखनऊ जेल में बंद सेंगर के भाई अतुल सिंह से भी लंबी पूछताछ हुई। एक टीम ट्रामा सेंटर भी गई। उधर, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फिर साक्ष्य जुटाए।

सीबीआइ की एक टीम दोपहर करीब 1:50 बजे सीतापुर जेल पहुंची और विधायक सेंगर से छह घंटे तक पूछताछ की। विधायक से सवाल-जवाब के दौरान सीबीआइ ने यह जानने का प्रयास किया कि उससे मिलने जेल में कौन-कौन लोग आते रहे हैं। उन्नाव पुलिस के निरीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा, माखी थाने के ड्यूटी मुंशी इरशाद खान, पीड़िता की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में निलंबित गनर सुदेश कुमार, महिला सिपाही रूबी व सुनीता देवी समेत छह पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई। अब तक सामने आए तथ्यों का सीबीआइ सिलसिलेवार परीक्षण कर रही है। (पेज-5 भी देखें)

पंजाब में परिवार के पांच लोगों की हत्या के बाद की खुदकशी

जागरण संवाददाता, मोगा

- शादी के दबाव और शाप के डर से दिया वारदात को अंजाम

पंजाब के मोगा जिले के गांव नत्थूवाला गरबी में शुक्रवार रात 25 वर्षीय युवक ने शादी के दबाव और शाप के डर से परिवार के छह सदस्यों को सोते हुए गोलियों से भून डाला और खुद को गोली मार ली। दहला देने वाली इस घटना में युवक संदीप सिंह के माता, पिता, बहन और तीन वर्ष की भांजी समेत पांच की मौके पर मौत हो गई। 80 वर्षीय दादा गुरचरन सिंह की हालत गंभीर है। परिवार में अब वही अकेले सदस्य बचे हैं।

एसपी इनवेस्टिगेशन परमार ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त .32 बोर की रिवॉल्वर और सुसाइड नोट वाली डायरी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। सुसाइड नोट में संदीप ने लिखा है कि वह मामा के घर (फरीदकोट के अराइयां वाला) से रिवॉल्वर चोरी करके लाया था। पुलिस के मुताबिक संदीप ने सबसे पहले अपनी मां बिंदर कौर (58), पिता मंजीत सिंह (60), दादी गुरदीप कौर (80) व दादा गुरचरन सिंह पर गोलियां चलाईं। इसके बाद उसने 30 वर्षीय बहन अमनजोत कौर और फिर तीन साल की भांजी मनजीत कौर की हत्या की। आखिर में संदीप ने खुद को भी गोली मार ली।

नहीं करना चाहता शादी : पुलिस को मिले 19 पेज के सुसाइड नोट में संदीप ने लिखा है- 'मैं तनाव का शिकार है। दारू पीता हूं, विवाह नहीं करना चाहता। हमारे खेतों में पीर बाबा की जगह थी। हमें उसका शाप लगा है। यह जगह उसने किसी को बेच दी थी। शाप के अनुसार हमारे परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं परिवार का अकेला बेटा हूं। ऐसे में पूरा परिवार इस बोझ को सहन नहीं कर पाता।' संदीप ने होने वाली पत्नी राजदीप कौर से भी माफी भी मांगी है। लिखा है- राजदीप मैंनू माफ करीं.. मैं तेरा सबतों बड्डा गुनहगार हां, पर मैं मजबूर हां, तेरी जिंदगी, खराब नहीं कर सकदा सी।

परिवार कर रहा था शादी की तैयारी : संदीप का परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। 12 सितंबर को उसकी शादी होने वाली थी। रविवार को संधारा (सावन के महीने में बहू को दिए जाने वाला शगुन का सामान) लेकर जाना था। इसके लिए वह एक दिन पहले ही बहन अमनजोत कौर व तीन साल की भांजी को लेकर आया था।

मालदीव पहुंचते ही गिरफ्तार हुए गफूर

तूतीकोरिन, प्रेट्र : मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर आखिरकार वापस चले गए। वह शुक्रवार रात अपनी बोट से भारत की जल सीमा से बाहर चले गए। शनिवार को मालदीव पहुंचते ही उन्हें वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भारत सरकार ने राजनीतिक शरण की गफूर की मांग ठुकरा दी। वह वैध दस्तावेज के बगैर गुरुवार को भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और देश में आने की कोशिश कर रहे थे।

गंभीर आरोपों के बीच मालदीव छोड़ने वाले गफूर को भारत सरकार ने अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। वह समुद्र के बीच अपनी बोट पर बने रहे, भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने वहीं जाकर उनसे पूछताछ की। इसी दौरान पता चला कि उनके पास यात्रा संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था और वह बिना सूचना के भारत आए थे। इसके बाद नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में विचार-विमर्श के बाद उन्हें वापस लौटाने का फैसला किया गया। इस दौरान गफूर ने मालदीव में अपनी जान का खतरा बताते हुए राजनीतिक शरण की भी मांग की, लेकिन भारत सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने साफ किया है कि भारत ने गफूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। न उन्हें हिरासत में लिया और न ही उनके साथ कोई जबर्दस्ती की गई।

बनी बात

सहारनपुर की नसीमा को उसके पति ने धमकी देकर घर से निकाल दिया था, लेकिन नया कानून बन जाने के बाद उसे जेल जाने का भय सताया तो कर लिया समझौता

तत्काल तलाक कानून के असर से फिर बसा नसीमा का घर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

तत्काल तीन तलाक कानून (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून) लागू होने के बाद संभवतः यह पहला मामला है जब इसके असर से एक टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। इस कानून का ही प्रभाव रहा कि आठ माह से मायके में रह रही और ससुरालियों की सताई नसीमा का घर एक बार फिर बस गया। पति और ससुर ने लिखकर दिया कि कानूनी कार्रवाई और तीन साल की जेल से बचने के लिए वे समझौता करने के लिए राजी हैं। नसीमा को करीब आठ माह पहले मारपीट कर तलाक की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया गया था।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली नसीमा की शादी 22 अप्रैल 2015 को उत्तराखंड के निवासी मोहम्मद अली के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान किया जाने लगा। एक दिन पति ने मारपीट कर उसे तलाक देने की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया था। 12 जुलाई को नसीमा ने पति, सास, ससुर समेत छह लोगों को नामजद करते हुए एसएसपी सहारनपुर के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसी बीच उसकी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज से हुई। फरहा का साथ मिलने और तत्काल तीन तलाक बिल पास होने के बाद नसीमा को बल मिला कि वह अपनी लड़ाई जीत सकती है। अंततः शनिवार को ससुराल पक्ष के लोग सहारनपुर आए और लिखित रूप से समझौता करने के बाद नसीमा को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए। समझौते में मांग के मुताबिक उसके ससुर ने नसीमा के नाम पर 750 वर्गफीट के प्लॉट का बैनामा करने की बात मान ली है। नसीमा के तीन साल के जुड़वां बच्चे हैं। पति और पत्नी के बीच हुए समझौते के दौरान अधिवक्ता फरहा फैज भी मौजूद थीं।

सहारनपुर में अधिवक्ता फरहा फैज और अपनी पत्नी के साथ मोहम्मद अली। जागरण

शौहरों ने दिया तलाक पीड़िताएं पहुंचीं थाने

लखनऊ : रायबरेली में एक शौहर ने बीवी को विदेश से फोन करके तीन तलाक कह दिया, जबकि लखीमपुर में शौहर पहले पत्नी को पीटते हुए घर के बाहर लाया और फिर सभी के सामने तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। इसे कानून का असर कह सकते हैं कि पीड़िताएं भी खामोश नहीं बैठीं। इंसाफ मांगने पुलिस के पास पहुंच गईं। रायबरेली वाले मामले में पुलिस ने अभी केस नहीं दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक तलाक और उत्पीड़न के सिलसिले में शिकायत मिली है और पति को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद ही पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह लखीमपुर के मामले में भी पुलिस ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। थाना दिवस पर पीड़िता ने उत्पीड़न की शिकायत की है। पति पर पिटाई का भी आरोप है।

हड़ताल का कहर, चंडीगढ़ पीजीआइ में 34 की मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ पीजीआइ के आइसीयू में भर्ती लुधियाना के 46 वर्षीय किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज राजकुमार की शनिवार सुबह मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे मरीजों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। परिजनों की रोने बिलखने की आवाज से ट्रामा और इमरजेंसी यूनिट में कोहराम मच गया। शाम सात बजे तक 34 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इनमें पांच दुर्घटना और 29 बीमारियों से ग्रस्त मरीज थे। इस बीच, रेजिडेंट डाक्टरों ने सोमवार से आंदोलन और तेज करने की धमकी दी है।

सामान्य दिनों में पीजीआइ में मरीजों की मौत का आंकड़ा औसतन 10 से 12 तक रहता है। आइसीयू, इमरजेंसी और ट्रामा के पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि पीजीआइ के ट्रामा, इमरजेंसी और लगभग सभी ऐसी इमरजेंसी यूनिट के मरीज सीनियर रेजिडेंट की देखरेख में होते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया था। इसलिए मौत की संख्या अचानक इतनी ज्यादा हो गई।

पीजीआइ में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण शनिवार को ओपीडी सेवा ठप रही। एक भी नए मरीज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जबकि सामान्य दिनों में आठ से यहां दस हजार मरीजों का इलाज होता है। यहां चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली के मरीज इलाज कराने आते हैं। हालांकि पीजीआइ प्रशासन ने ओपीडी में सैकड़ों मरीजों के इलाज किए जाने का दावा किया है।

> पीजीआइ केवल चंडीगढ़ ही नहीं हरियाणा और पंजाब का भी मुख्य रेफल सेंटर है। यहां अति गंभीर मरीज रेफर किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहां मरीजों की मौत के मामले में हड़ताल और सामान्य दिनों की स्थिति के बीच तुलना करना उचित नहीं होगा।
>
> **- प्रोफेसर जगत राम, निदेशक चंडीगढ़ पीजीआइ**